ToT

(B)

Monetisation

मौद्रिकरण

Operation & Maintenance

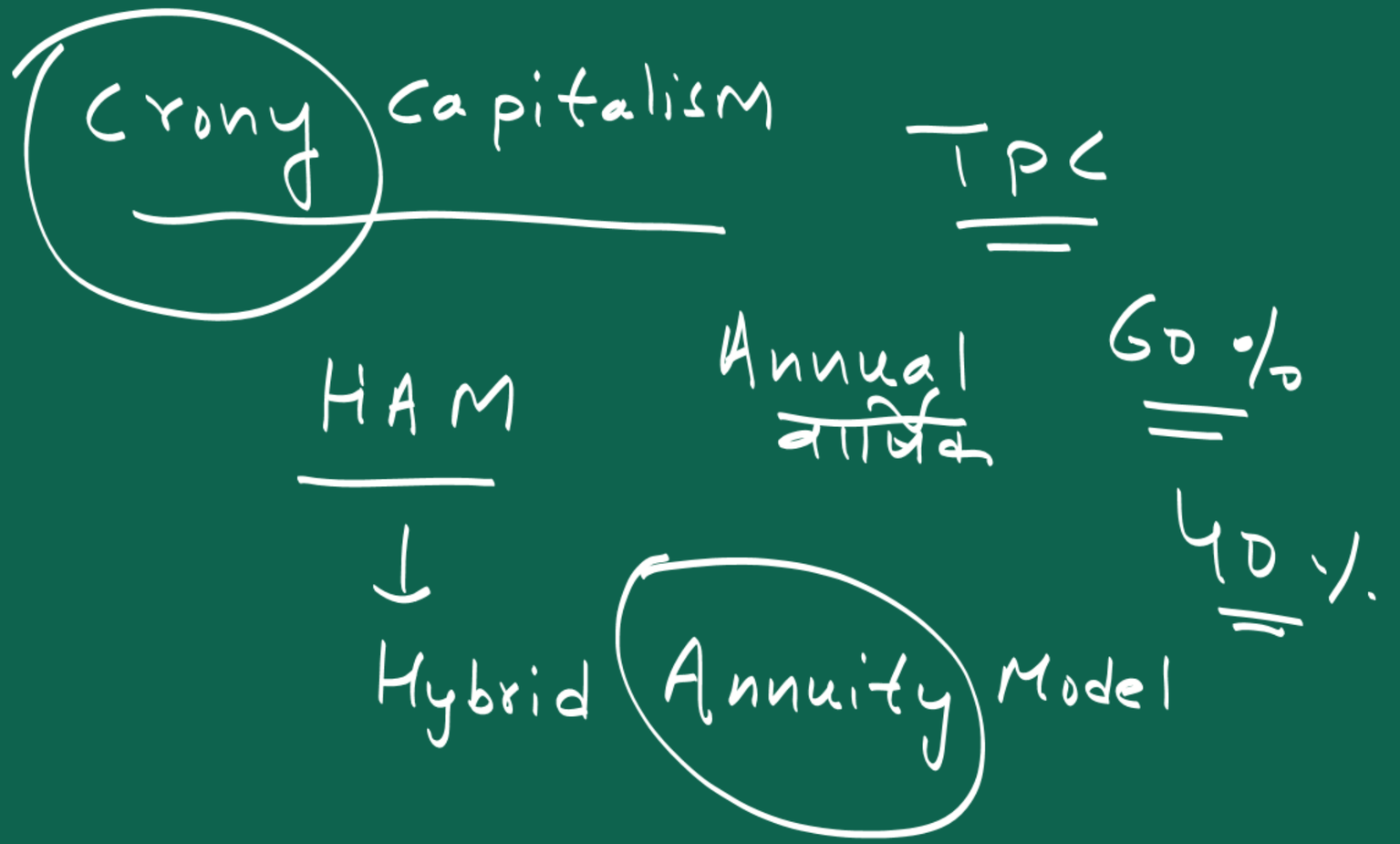

Crony Capitalism

TPC

Annual
वार्षिक

60 %

HAM
↓
Hybrid Annuity Model

40 %

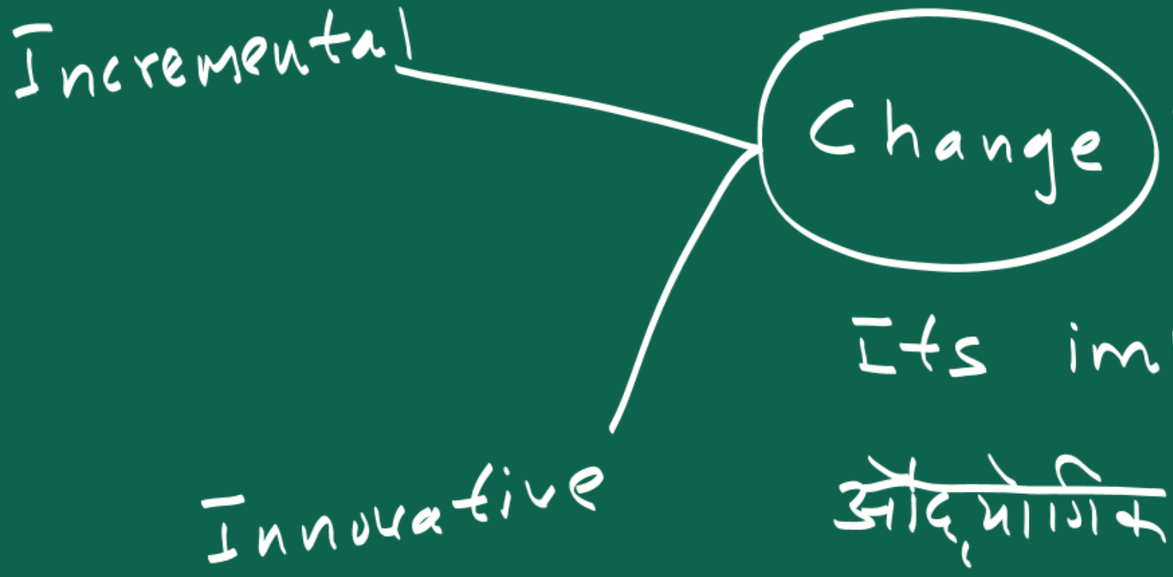

Change in Industrial Policy
&
Its impact on Industrial Growt

औद्योगिक नीति में परिवर्तन
और
औद्योगिक संवृद्धि पर उसका प्रभाव

प्रस्तावना –

किसी भी देश की औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है।

यह निर्धारित औद्योगिक विकास की परिचायक होती है।

इसके अभाव में कार्यक्रमों, निर्णयों, कानूनों, व्यवस्थाओं को दिशा नहीं मिल पाती है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

भारत में औद्योगिक नीतियों की घोषणा की शुरुआत सबसे पहले 1948 में की गई और अब तक 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है -

(i) 1948
(ii) 1956
(iii) 1973
(iv) 1977
(v) 1980
(vi) 1991

इन सभी औद्योगिक नीतियों में 1991 की औद्योगिक नीति को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है।

नई औद्योगिक नीति

New Industrial Policy

कार्य

It is not the business of the govt. to do business.

↓

व्यवसाय/धन्धा

1. औद्योगिक लाइसेन्सिंग को समाप्त किया गया -

वर्तमान में निम्न चार क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेन्स की आवश्यकता पड़ती है -

(i) औद्योगिक विस्फोटक ।
(ii) खतरनाक रसायन ।
(iii) सिगरेट, सिगार, तम्बाकू से बने पदार्थ आदि ।
(iv) रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐरोस्पेस

२. सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों

↓

Reserved

को कम किया गया ।

↓

वर्तमान में –

(i) आण्विक ऊर्जा और आण्विक खनिज ।

(ii) रेल परिवहन ।

3. नई विनिर्माण कम्पनियों के लिए PMP को हटाया गया।

↓

Phased Manufacturing Programme

↓

विनिर्माता कम्पनियों को यह बताना पड़ता था कि वे कब तक चरण-2 आयातित कच्चे माल के स्थान पर स्वदेशी कच्चे माल का प्रयोग शुरू कर देंगी।

५. अनिवार्य परिवर्तनीयता की शर्त को हटाया गया।

↓

ऋणों का इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तन।

5.

औद्योगिक स्थानीयकरण की नीति को ढ़ीला किया गया।

↓

10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में किसी भी उद्योग को खोला जा सकता है।

हालाँकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से 25 किलोमीटर की दूरी तक प्रदूषणकारी उद्योग नहीं खोले जा सकते हैं।

6. विदेशी निवेश और तकनीकि का उदारीकरण -

वर्तमान में कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में FDI लाया जा सकता है।

औद्योगिक संवृद्धि पर प्रभाव : Post liberalisation Period

↓

Dismal

निराशाजनक

↓

GDP की ग्रोथ रेट से भी कम औद्योगिक ग्रोथ रेट का औसत स्तर रहा है।

(i) विश्व-स्तरीय इन्फ्रा की कमी।

(ii) भारत में जटिल श्रम-कानून।

(iii) भारत में EODB का स्तर अच्छा नहीं होना।

↓

Ease of Doing Business

(iv) भारत में नई तकनीकि को धीमी गति से लागू करना।

(v) श्रम उत्पादकता का कम होना।

(vi) व्यापार सम्बन्धी चुनौतियां

↓

चीन और FTA

राष्ट्र ।

+

विकसित राष्ट्रों का संरक्षणवाद

(vii) R&D पर कम निवेश।

↓

Research &
Dev.

↓

Innovative Products

Public + Private दोनों —

GDP का
↓
0.67%

उपर्युक्त के अलावा, शराब के लिए
लाइसेन्स राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है।

उदारीकरण
↓
उदार करना
↓
कठोर नियम / नियन्त्रण